

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के संबंध में सर्वेक्षण

296. डॉ. उदित राज:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अ.जा. उद्यमियों की संख्या जानने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार का अध्ययन/सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने 67वें दौर में जुलाई, 2010 से 2011 के दौरान देश में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम(i) तथा 2एम(ii) के अंतर्गत पंजीकृत विनिर्माण उद्यमों, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सहकारी समितियां और निर्माण में लगे सेवा क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर विनिर्माण, व्यापार और प्रोपराइटर एवं भागीदारों द्वारा संचालित अन्य सेवाओं से संबंधित गैर-कृषिगत उद्यमों के संबंध में एक बड़े पैमाने का नमूना सर्वेक्षण संचालित कराया था।

इस सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, 13.4% उद्यम अनुसूचित जाति श्रेणी से संबद्ध थे। विनिर्माण और व्यापार से संबंधित उद्यम क्रमशः 13.5% तथा 11.8% अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं।

\*\*\*\*\*